

## प्रतस्पर्द्धा (संशोधन) वधियक, 2022

### प्रलिमिंस के लयि:

CCI, प्रतस्पर्द्धा अधनियिम 2002, राष्ट्रिय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (NCLT) ।

### मेन्स के लये:

बाज़ार की गतशीलता में परविरतन के कारण प्रतस्पर्द्धा आयोग का महत्त्व ।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [प्रतस्पर्द्धा अधनियिम, 2002](#) में संशोधन करने वाला वधियक [लोकसभा](#) में पेश कया गया ।

### संशोधन की आवश्यकता:

- नयी पीढ़ी का बाज़ार:
  - तकनीकी प्रगति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कीमत एवं अन्य कारकों के बढ़ते महत्त्व के कारण बाज़ार की गतशीलता तेज़ी से बदली है, बाज़ार की प्रतस्पर्द्धा को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लयि ये संशोधन अपरहिर्य हो गए थे ।
- अधगिरहण का मद्दा:
  - अधनियिम की धारा 5 के अनुसार वलिय, अधगिरहण या समामेलन में शामिल पक्षों को केवल परसिंपत्तिया कारोबार के आधार पर संयोजन की गतविधि के वषिय में भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग सूचति करने की आवश्यकता है ।
- गन जंपगि:
  - ऐसी स्थति में दो या दो से अधिक संयुक्त पक्ष अनुमोदन से पूर्व अधसूचति लेन-देन बंद कर देते हैं अथवा आयोग के संज्ञान में लाए बगैर लेन-देन की प्रक्रया का समापन करते हैं ।
- हब-एंड-स्पोक कार्टेल:
  - हब-एंड-स्पोक व्यवस्था एक प्रकार का व्यापारिक गुट है जसिमें ऊर्ध्वाधर रूप से संबंधति हतिधारक एक हब के रूप में कार्य करते हैं और आपूरतकिर्त्ताओं या खुदरा वकिरेताओं पर कर्षतजि प्रतबिंध लगाते हैं ।
    - वर्तमान में प्रतस्पर्द्धा-वरीधी समझौतों पर प्रतबिंध केवल समान व्यापार वाली संस्थाओं को शामिल करता है जो प्रतस्पर्द्धा-वरीधी गतविधियों में संलग्न हैं ।
    - यह वतिरकों और आपूरतकिर्त्ताओं द्वारा ऊर्ध्वाधर शृंखला के वभिनिन स्तरों पर संचालति हब-एंड-स्पोक कार्टेल की उपेक्षा करता है ।

### प्रस्तावति संशोधन:

- सौदे के मूल्य की अवसीमा:
  - नए वधियक में सौदे के मूल्य की अवसीमा का प्रावधान भी प्रस्तावति है ।
    - इसके अलावा 2,000 करोड रुपए से अधिक के सौदे मूल्य वाले कसी भी लेन-देन के वषिय में आयोग को सूचति करना अनविर्य होगा यर्द दोनों पक्षों में से कसी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन है ।
- पर्याप्त व्यवसाय संचालन:
  - आयोग कसी उद्यम के भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हेतु आकलन और आवश्यकताओं को नरिधारति करने के लयि वनियिम तैयार करेगा ।
    - यह आयोग के समीक्षा तंत्र को सशक्त करेगा, वशिष रूप से डिजिटल और बुनयादी ढाँचे के कषेत्र में , जनिमें से अधकिंश की पहले रपिर्टगि नहीं की गई थी, क्योंकि ये परसिंपत्तिया कारोबार मूल्य कषेत्राधिकार की सीमा को पूरा नहीं करते थे ।
- संयोजन की गत को तीवर करना:

- किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिये जो एक संयोजन नष्टिपादति करना चाहता है, उन्हें इस वषिय में आयोग को सूचति करना होगा।
- पहले आयोग को संयोजन को मंजूरी प्रदान करने के लिये **210 कार्य दविस की समय-सीमा** नरिधारति थी, जिसके बाद यह स्वतः स्वीकृत हो जाता था।
  - नए संशोधन ने समय सीमा को 210 कार्य दविसों से घटाकर केवल **150 कार्य दविसों और 30 दिनों की वसितार** अवधि को नरिधारति कर दिया है।
    - यह **संयोजनों की मंजूरी में तेज़ी** लाएगा और आयोग के साथ संयोजन-पूर्व परामर्श के महत्त्व को बढ़ावा देगा।

#### ■ गन जंपगि:

- पहले गन-जंपगि के लिये जुर्माना संपत्तिया कारोबार का कुल 1% था जिससे अब सौदे के मूल्य का 1% कयि जाने का प्रस्ताव है।

#### ■ खुले बाज़ार में खरीदारी की छूट:

- यह आयोग को अग्रमि रूप से सूचति करने की आवश्यकता से **खुले बाज़ार की खरीद और शेर बाज़ार के लेन-देन में छूट** देने का प्रस्ताव करता है।

#### ■ हब-एंड-स्पोक कार्टेल:

- संशोधन उन संस्थाओं को चहिनति के लिये 'प्रतीसुपर्द्धा-वरिधी समझौतों' के दायरे को वसितृत करता है जो कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, भले ही वे समान व्यापार प्रथाओं में शामिल न हों।

#### ■ मामलों का नपिटान और प्रतबिद्धताएँ:

- नया संशोधन **ऊर्धवाधर समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग** से संबंधति मामलों के नपिटान और प्रतबिद्धताओं के लिये एक रूप-रेखा का प्रस्ताव करता है।
  - **ऊर्धवाधर समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग** के मामले में, **महानदिशक (DG)** द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले दोनों पक्ष प्रतबिद्धता के लिये आवेदन कर सकती हैं।
    - **संशोधन के अनुसार**, मामले में सभी हतिधारकों का पक्ष सुनने के बाद **प्रतबिद्धता या नपिटान** के संबंध में आयोग का नरिणय अपील योग्य नहीं होगा।

#### ■ अन्य प्रमुख संशोधन:

##### ◦ उदारता का प्रावधान:

- यह आयोग को आवेदक को दंड की अतरिकित छूट देने की अनुमति देता है जो एक असंबंधति बाज़ार में दूसरे कार्टेल की उपस्थिति का खुलासा करता है, बशरते सूचना आयोग को कार्टेल के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया राय बनाने में सक्षम बनाती हो।

##### ◦ महानदिशक की नयिकृति:

- केंद्र सरकार के बजाय आयोग द्वारा **महानदिशक की नयिकृति आयोग को अधिकि नयितरण प्रदान करती है।**
  - यह आयोग को अधिकि नयितरण देता है।

##### ◦ जुर्माने के संबंध में दशानरिदेश:

- आयोग वभिनिन प्रतसिपर्द्धा उल्लंघनों के लिये **दंड की संख्या के संबंध में दशानरिदेश जारी करेगा।**
  - आयोग के आदेश के खलिफ **राष्ट्रीय कंपनी कानून नयायाधिकरण (NCLT)** द्वारा अपील पर सुनवाई के लिये पार्टी को जुर्माना राशिका 25% जमा करना होगा।

## आगे की राह

- नए परिवर्तनों के साथ आयोग को नए युग के बाज़ार केकुछ पहलुओं का प्रबंधन करने एवं इसके संचालन को और अधिकि मज़बूत बनाने में सक्षम होना चाहिये।
  - प्रस्तावति परिवर्तन नसिंदेह आवश्यक हैं, **हालाँकि ये आयोग द्वारा बाद में अधिसूचति नयिमों पर अत्यधिकि नरिभर हैं।**
  - इसके अलावा सरकार को यह समझना चाहिये कि बाज़ार की गतशीलता लगातार बदल रही है, इसलिये कानूनों को नयिमति रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता है।

## भारतीय प्रतसिपर्द्धा आयोग

#### ■ परिचय:

- **भारतीय प्रतसिपर्द्धा आयोग (CCI)** की स्थापना मार्च, 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतसिपर्द्धा अधनियिम, 2002 के तहत अधनियिम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिये की गई थी।
  - यह मुख्य रूप से बाज़ार में **प्रतसिपर्द्धा-वरिधी प्रथाओं** के तीन मुद्दों का अनुसरण करता है:
    - **प्रतसिपर्द्धा वरिधी समझौते।**
    - **प्रभुत्व का दुरुपयोग।**
    - **संयोजन।**

#### ■ उद्देश्य:

- प्रतसिपर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना।
- प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हतियों की रक्षा करना।
- भारत के बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनशिचति करना।
- नमिनलखिति के माध्यम से मज़बूत प्रतसिपर्द्धा माहौल स्थापति करना:
  - उपभोक्ताओं, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों सहति सभी हतिधारकों के साथ सक्रयि जुड़ाव।

■ संरचना:

- प्रतस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - आयोग **अर्द्ध-न्यायिक निकाय** है जो वैधानिक अधिकारियों को सलाह देता है और अन्य मामलों से भी नपिटता है।
  - अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ):

प्रश्न. अर्द्ध-न्यायिक निकाय क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से देश के शासन में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2016)

**स्रोत: द हट्टि**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-competition-bill-2022>

